Statement-II

Sector wise allocation of Plan outlay for the Annual Plan 1994 95 of Gujarat

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Sector	Annual Plan 1994 95 Approved Outlay
1.	Agriculture & Allied Activities	13330.50
2.	Rural Development	8195.50
3.	Special Area Programmes	0.00
4.	Irrigation & Flood Control	39683.00
5.	Energy	49890.00
6.	Industry & Minerals	12597.50
7.	Transport	10217.00
8.	Communications	165.00
9.	Science, Technology & Environment	105.00
10.	General Economic Services	4366.50
11.	Social Services	65382.00
12.	General Services	68.00
	TOTAL :	224000.00

हानि में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम

3223. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लगातार घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिये कोई नीतिगत फैसला लिया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस योजना पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर) गमंग : (क) 1991–92 से 1993–94 तक के पिछले 3 वर्षों में 83 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लगातार घाटे में चल रहे हैं ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुन: स्थापन और उनके कार्य में सुधार हेतु और आधुनिकीकरण और विविधीकरण स्कीमों के माध्यम से उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) घाटे में चल रहे उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नही की गई है । इनमें से प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाता है । और उनके लिए वार्षिक योजनाओं में उपयुक्त प्रावधान किए जाते है।

Classification of Hill Areas in the States

3224. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to states:

(a) whether it is a fact that a Technical Committee of the Working Group constituted by the Planning Commission in the last decade made suggestion about the classification of hill areas in the States;

(b) if so, whether the hill areas have been identified according to this definition;

(c) what are the hill areas identified in Madhya Pradesh as per the recommendations of the Technical Committee; and

(d) whether these areas will be considered for central assistance on par with the hill areas of the border States?